an>

Title: Regarding visa for investment of trade in USA.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय को उठाने जा रहा हूँ, इस भारत भर के लाखों नौजवान और विदेशों में जो लोग रहते हैं, खास कर अमरीका में जितने भी भारतीय रहते हैं, वे वहां पर यदि कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो तरह-तरह की मुश्किलें आती हैं। खास कर अमरीका में व्यापार और निवेश करना हो तो बाकी पूरे विश्व को देखा जाए तो लगभग 80 देश ऐसे हैं, जिनको इ-1 और इ-2 वीज़ा के तहत वहां पर मान्यताएं मिलती हैं, जिनमें चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ऐसे देश भी शामिल हैं। परंतु भारत जहां पर 125 करोड़ की आबादी का यह देश है और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय अमरीका में रहते हैं और जब उन्हें कोई व्यवसाय करना होता है, तो वह इ-1 और इ-2 वीज़ा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि हमारे भारत की और अमरीका की कोई ऐसी संधि हुई नहीं है। वर्तमान के अंदर यदि कोई करना चाहता है तो एल-1 और इबी-5 श्रेणी का वीज़ा उपलब्ध है। अब इन दोनों के वीज़ा के लिए यदि हम देखते हैं तो इ-1 और इ-2 श्रेणी की अपेक्षा नियमों में एल-1 और इबी-5 वीज़ा बहुत ज्यादा सख्त है। यदि कोई इसके अंदर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, इबी-5 श्रेणी का वीज़ा प्राप्त कर के यदि निवेश करता है तो कम से कम पांच लाख डॉलर या दस लाख डॉलर का निवेश हो, तब जा कर वह कर पाता है। बाकी ई-टू श्रेणी के अंदर तो केवल पचास हजार का निवेश करके वह कर सकता है, तो यह जो भेदभाव है, जिसकी वजह से भारतीय इंटरप्रिन्योर जितने भी विदेश में जाकर व्यवसाय करना चाहते हैं, इस भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। एल-वन वीजा के अंदर ऐसा है कि कम से कम एक वर्ष तक वहाँ पर व्यवसाय का अनुभव हो और कई तरह की ऐसी मुश्किलें वहाँ पर होती हैं। अब अमेरिका की टीवी चैनल्स पर भी इसकी बहुत बहस हुई है और बहस होने के बाद एक ऐसी मान्यता बनी है कि हाल ही में पूर्ण बहुमत से जीती हुई भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है, जिन्होंने विश्व भर के अंदर ऐसी उपलब्धियां पाई हैं और अच्छे रिश्ते हुए हैं, तो यही सरकार है, जो यह सन्धि कर सकती है, जिससे लाखों भारतीयों को, वहाँ रहने वाले भारतीयों को व्यवसाय करने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय से निवेदन करता हूँ कि यह वार्ता आगे बढ़े और ऐसी सन्धि हो, जिससे लाखों भारतीय युवाओं को एक अच्छा मौका मिलेगा। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Manoj Rajoria, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Mahesh Girri.